सुर्खियों में क्वाड

लेखक - सुजन आर चिनॉय (महानिदेशक, इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एंड एनालाइसिस, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

7 नवंबर, 2019

"भारत-प्रशांत क्षेत्र में चतुर्भुज वार्ता प्रक्रिया से भारत को होने वाले फायदों को लेकर चीन चिंतित है।"

22 अक्टूबर को हेरिटेज फाउंडेशन के एक भाषण में, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 'क्वाड' से 'चीन का स्थान दुनिया में यथावत बना रहेगा।' चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने 25 अक्टूबर को अमेरिका के इस बयान की निंदा करते हुए झूठा और बेतुका बताया। अमेरिका और चीन के बीच इस तरह का युद्ध अब नियमित हो गया है। फिर भी, सभी का ध्यान क्वाड के भविष्य पर है, जिसे 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में हाई-प्रोफाइल मीटिंग के एक महीने बाद 4 नवंबर को बैंकॉक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर फिर से आयोजित किया गया। सितंबर की बैठक विदेश मंत्रियों के स्तर पर पहली थी।

जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा 2007 की शुरुआत में एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी और भारत और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा समर्थित था। सिंगापुर के साथ 2007 में एक समुद्री अभ्यास में जब ये चार देश मिले थे, तब भी एक सामान्य समझ थी कि ये चार देश अपने सैन्य आयामों को किसी भी देश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे। हालाँकि, चीन में सामरिक समुदाय ने इसे एक उभरती हुई 'एशियाई नाटो' के रूप में प्रदर्शित किया था, जो सामुद्रिक चिंताओं के साथ शुरू हुआ और धीरे-धीरे चीन द्वारा चीन को लक्षित करने के लिए एक व्यापक इंडो-पैसिफिक मंच का उपयोग करने के रूप में देखा जाने लगा। उस वर्ष, भारतीय संसद को अबे के 'दो सागरों के संगम' संबोधन ने इस नए अवधारणा को एक नया बल प्रदान किया। अबे ने हिंद और प्रशांत महासागरों के संगम पर एक ष्व्यापक एशियाष् की नई परिभाषा की बात की थी। इसने भारत के आर्थिक उदय को मान्यता दी और प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संपूर्णता में फैले एक विशाल नेटवर्क के हिस्से के रूप में जापान और भारत को एक साथ लेकर आया। इसे एक खुले और पारदर्शी नेटवर्क के रूप में देखा गया जो लोगों, वस्तुओं, पूँजी और ज्ञान को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देता है।

पीएम केविन रुड के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया की चीनी संवेदनशीलता के कारण क्वाड का विघटन हो गया। फिर भी, चीन का संदेह दिसंबर 2012 में एशिया के 'डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड' में अबे के संदर्भ के साथ फिर से शुरू हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं जो हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में समुद्री कॉमन्स की सुरक्षा करते हैं। राष्ट्रपति ओबामा की पुनःसंतुलन या एशिया नीति के प्रति झुकाव, जो कभी भी लागू नहीं हुआ, का उद्देश्य केवल 2013 के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में दक्षिण चीन सागर में चीन के अतार्किक दावों पर तुरंत कार्रवाई करने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का प्रतिरोध करने से संबंधित था।

पिछले दो वर्षों में क्वाड देशों के बीच अंतर कम हुआ। एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी क्षेत्रीय वास्तुकला, सड़क के नियम, नेविगेशन की स्वतंत्रता और अधिक उड़ान और आसियान की केंद्रीयता के निर्माण के लिए सामान्य संदर्भ हैं। यहाँ विचारणीय तथ्य यह है

कि चीन के उदय से जूझ रहे सभी राष्ट्र लोकतांत्रिक नहीं हैं।

यहाँ तक कि पूर्व में जब अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और भारत-प्रशांत रणनीति पर पेंटागन की रिपोर्ट में रूस के साथ चीन का उल्लेख एक संशोधनवादी शक्ति और एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में किया, तब जापान ने चीन के साथ बेहतर संबंधों के लिए अपने स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक से 'रणनीति' शब्द को हटा दिया। समृद्धि के लिए चीन पर अपनी अत्यधिक आर्थिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के श्वेत पत्र ने चीन के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करने में सावधानी बरती है।

चीन का मानना है कि इंडो-पैसिफिक और विशेष रूप से क्वाड की अवधारणा, अमेरिका द्वारा रची गई एक भयावह साजिश है, जिसका उद्देश्य बीआरआई का विरोध करना है, इसके विकासात्मक वित्त और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर सवाल उठाना है। चीन मानता है कि अमेरिका, जापान तथा भारत और अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा त्रिपक्षीय समझौता एक हानिकारक विकास की शुरुआत है।

चीन एक समावेशी क्षेत्रीय सहकारी संरचना के निर्माण के लिए 'एशिया-प्रशांत' के प्रति वचनबद्ध है। चीन के लिए, 'इंडो-पैसिफिक' को अपनाने का तात्पर्य इसके पूर्व के क्षरण से है। हाल ही में, चीनी विद्वानों और अधिकारियों ने बदले हुए व्यवहार को दिखाया और इंडो-पैसिफिक और क्वाड के बीच विचार-विमर्श करने लगे। उप विदेश मंत्री कोंग जुआनौ ने 19 मार्च को जकार्ता में भारत-प्रशांत सहयोग पर एक उच्च-स्तरीय बातचीत में भाग लिया, जहाँ उन्होंने आसियान और चीन-आसियान सहयोग की केंद्रीयता को रेखांकित किया। अब यह स्पष्ट है कि चीन इसका विरोध करने की बजाय इंडो-पैसिफिक के प्रति देखो और इंतज़ार करो (wait-and-watch) का दृष्टिकोण अपना रहा है क्योंकि आसियान केंद्रीयता इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, जो चीनी हितों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, की धारणा को कमज़ोर कर सकती है।

चीन आसियान की केंद्रीयता को चीन पर केंद्रित सुरक्षा एजेंडे से भारत-प्रशांत को दूर रखने के एक अवसर के रूप में देखता है। बीआरआई पर एक साथ काम करने के लिए चीन के पाँच सूत्रीय फॉर्मूले ने अधिक प्रयास करने की कोशिश की, जिसमें चीन-आसियान डिजिटल सहयोग को शामिल किया गया, साथ ही इसमें 5 जी, चीन-आसियान एफटीए को पूरी तरह से लागू करना, आचार संहिता (चीन द्वारा प्रस्तावित) की बातचीत के आधार पर क्षेत्रीय नियमों को अंतिम रूप देना और संयुक्त समुद्री अभ्यासों में संलग्न होना (पिछले साल अक्टूबर से चीन और आसियान के बीच पहले से चला आ रहा) शामिल है।

चीन के प्रवक्ता ने कहा कि 3 नवंबर को बैंकॉक में चीन-आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रीमियर ली केकियांग और आसियान नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं और एक सहमत कार्यक्रम का पालन करते हुए आचार संहिता को आगे बढ़ाया है। प्रीमियर केकियांग ने बीआरआई और आसियान के विकास के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए भी काम किया है। आसियान कनेक्टिविटी 2025 पर मास्टर प्लान पर संयुक्त वक्तव्य और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहित तीन परिणाम दस्तावेज़ जारी किए गए। चीन ने मौजूदा आर्थिक गलियारों, चीन-थाईलैंड रेलवे, चीन-लाओस रेलवे और जकार्ता-बांडुंग हाई-स्पीड रेलवे सहित परिवहन मार्गों को आगे बढ़ाने के लिए आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

'रणनीतिक स्वायत्तता' के लिए भारत की प्रतिबद्धता आमतौर पर चीन को आश्वस्त कर रही है। यह बताता है कि भारत कभी भी चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ पूरी तरह से गठबंधन करने के लिए सहमत नहीं होगा। यह धारणा भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को मजबूत करते हुए, अब तक, वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में, चार में से तीन क्वाड राष्ट्रों तक सीमित है। भारत-प्रशांत व्यापार परिषद में भारत शामिल नहीं हुआ।

यह घटना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांगरी-ला कार्यक्रम में बीजिंग में दिए गए भाषण को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। समान रूप से, चीन यह नोट करने में विफल नहीं होगा कि यह भारत ने मंत्री स्तर पर क्वाड की बैठक करने की अनुमति दी है।

हालाँकि, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत का यह निर्णय तब आया जब चीन असफल रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू और कश्मीर तथा अनुच्छेद 370 मामले में पाकिस्तान का समर्थन करने का प्रयास कर रहा था।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच हाल ही में हुई मामल्लापुरम शिखर सम्मेलन एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो दोनों पक्षों के हितधारकों को रणनीतिक मार्गदर्शन देने के लिए महत्त्वपूर्ण है। जापान के साथ, चीन के लिए अवसर तीसरे देशों में सहमति-प्राप्त परियोजनाओं पर एक साथ काम करने और 2020 में जापान में शी जिनपिंग की प्रस्तावित यात्रा से लाभ कमाने से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया, जो अमेरिका का एक सहयोगी देश भी है, दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता में शामिल है।

चीन क्वाड और उसके भविष्य की रूपरेखा से सावधान रहेगा। चीन भारत-प्रशांत क्षेत्र में चतुर्भुज वार्ता प्रक्रिया से भारत को होने वाले फायदों को लेकर चिंतित है। स्वाभाविक रूप से, यह जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का उपयोग करने की कोशिश करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्वाड कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्षमता-निर्माण, एचएडीआर और समुद्री सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा और आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रीय समन्वय तंत्र से आगे ना बढ़े, ताकि यह 'एशियाई नाटो' न बन सकें। हालाँकि, बहुत कुछ चीन की कार्रवाइयों और इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे चीन की क्षमताओं और इरादों को कैसे समझते हैं।

GS World टीम...

क्वाड

क्या है?

- क्वाड के चतभुर्ज गठन में जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और इस क्षेत्रीय गठबंधन को ही क्वाड कहा जाता है।
- इस विचार को पहली बार जापानी प्रधान मंत्री शिन्जो आबे ने 2007 में पेश किया था।
- जिस प्रकार से दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और तीन देशों के मध्य त्रिपक्षीय संबंध बनते हैं, ठीक उसी प्रकार वार्तालाप और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से चार देशों का एक मंच पर आना एक बेहतर प्रयास है।
- इसका उद्देश्य पूर्ववर्ती 'एशिया-प्रशांत संकल्पना' के स्थान पर 'हिंद-प्रशांत संकल्पना को स्वरूप देना है।
- अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की यात्रा से भी यही लगता है कि वाशिंगटन की मंशा इस क्षेत्र में अधिक से अधिक संबंध मजबूत करने की है।
- यह नाटो की तरह का संगठन हो सकता है, जिसे 'रूस को बाहर रखने, अमेरिका को शामिल करने और जर्मनी का कद छोटा करने में' सफलता मिली थी। इसी कारण कई पर्यवेक्षकों ने इस नए संगठन को चीन को घेरने के एक औजार के रूप में परिभाषित किया है।
- हालांकि एक प्रभावशाली संगठन बनने के लिए इसे नाटो के नक्शेकदम पर भी चलना चाहिए, यानी उसे 'चीन को बाहर यह चतुष्कोणीय गठबंधन इस सामरिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के बीच 'मुक्त' रखने में महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

भारत के लिए महत्त्वपूर्ण क्यों?

- क्वाड को फिर से जिंदा करने की कई वजहें हैं। चीन के साथ हुए डोका-ला विवाद और बाद में 'बेल्ट रोड इनिशिएटिव' ने भारत को इसके लिए प्रोत्साहित किया, तो ऑस्ट्रेलिया और कुछ हद तक जापान के लिए ऐसा करने की बड़ी वजह द्वि पक्षीय गठबंधन के प्रति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की प्रतिबद्धता और 'क्वाड' के वायदों के तहत उन्हें मजबूत बनाने की मंशा है।
- यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस क्षेत्र को लेकर वाशिंगटन की प्रतिबद्धता महज कहने भर की न रह जाए, बल्कि वह इसके लिए गंभीर भी बने।
- इंडो-पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल समुद्री जीवविज्ञानी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर से लेकर पश्चिम व मध्य प्रशांत महासागर तक पसरे पानी के विस्तार को परिभाषित करने के लिए करते रहे हैं।

- मगर 21वीं सदी की शुरुआत में इस शब्द को भू-राजनीतिक शब्दावली में जगह मिली और यहाँ अपनी वैज्ञानिक परिभाषा से कहीं अधिक विवादास्पद साबित हुआ।
- यह क्षेत्र 20वीं सदी में विभिन्न देशों और एक ही मुल्क के अलग-अलग राज्यों के बीच खूनी संघर्षों का गवाह तो बना ही, विफल, संभावित और स्थापित परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच निकट भविष्य में तनाव के बीज भी यहां खूब दिखते हैं।
- एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के न होने से यहाँ ऐसे तनाव की आशंका ज्यादा है। इस लिहाज से चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता (क्वाड) को फिर से जीवंत करने की कोशिशों को देखें, तो यह एक उल्लेखनीय कदम है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में 4 नवम्बर को क्वाड की मंत्रिस्तरीय बैठक बैंकाक में सम्पन्न हुई है।
2. इस बैठक का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले, और समावेशी प्रयास पर परामर्श करना था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements in context to quadrilateral security dialogue (quad)-

1. Recently on November 4, the Quad Ministerial meeting was held in Bangkok.
2. The purpose of this meeting was to consult on free, open, and inclusive effort in the Indo-Pacific region.

Which of the above statement is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) None of these

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक साझेदारी की दिशा में क्वाड समूह (अमेरिका, भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया) की बढ़ती गतिविधियों के क्या निहितार्थ हैं? चीन और भारत के संदर्भ में विशेष चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

What are the relevence of the growing activities of the Quad Group (America, India, Japan and Australia) towards strategic partnership in the Asia-Pacific region? Discuss specifically in the context of China and India. (250 words)

नोट : 6 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।